(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पदों को भरने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन रिक्त पद को कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) से (ग) 1989-90 से श्रम मंत्रालय और स्वायत्त निकायों सहित इसके कार्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर 940 अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं । 1991-92 के आरम्भ में श्रम मंत्रालय तथा स्वायत्त निकायों सहित इसके कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 423 अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के पद रिक्त थे । इन पदों में से लगभग 55% पदों पर 30-4-1992 तक नियुक्तियां हो चुकी थी । आरक्षित पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है ।

श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

2079. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सड़क परिवहन उद्योग से सम्बन्धित श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने के लिए इस उद्योग के संबंध में एक राष्ट्रीय औद्योगिक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवर) : (क) और (ख) औद्योगिक समिति का कार्य पक्षों के बीच समस्याओं पर बेहतर तालमेल स्थापित करने, समस्याओं के समाधान के लिए सलाह देने तथा विचारों के मतैक्य पर पहुंचने के उद्देश्य से संबद्ध उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उस पर विचार-विमर्श करना है। बाद में सड़क परिवहन से संबंधित औद्योगिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिससे यह उद्योग की रुग्णता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर सके तथा उन समस्याओं को दूर करने के उपाय सुझा सके। समिति का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

औद्योगिक नीति के श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव

अध्यक्ष — श्री पी० ए० संगमा कोयला राज्य मंत्री

(i) **सरकार**

(क) **केन्द्र सरकार**

1. श्रम मंत्रालय	1 सीट
2. भूतल परिवहन मंत्रालय	1 सीट
योग	2 सीट

(ख) **राज्य सरकारें**

आंध्र प्रदेश, गुजरात जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	6 सीट (प्रत्येक को एक सीट)

(ii) **नियोजक**

1. कलकत्ता स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट
2. यू०पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट
3. महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	1 सीट

4. ग्राल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली	1 सीट
5. इंडियन रोडस एण्ड ट्रांसपोर्ट डेव० एसो० बम्बई	1 सीट
6. भारतीय नियोजक परिषद	2 सीट
योग	7 सीट

(iii) कर्मकार

1. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	2 सीट
2. भारतीय मजदूर संघ	2 सीट
3. हिन्द मजदूर सभा	1 सीट
4. इंडियन ट्रेड यूनियनस् केन्द्र	1 सीट
5. ग्राल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1 सीट
योग	7 सीट

Bill for construction workers

2080. **SHRI CHATURANAN MISHRA:** Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to introduce a fresh and a comprehensive Bill for construction workers;

(b) if so, whether recommendation of the 12th report of the 8th Lok Sabha on construction workers will be taken into consideration while formulating the said Bill;

(c) whether Government propose to consult the National Campaign Committee on Central Legislation for construction labour headed by Justice V. R. Krishna Iyer before finalising the Bill; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SING GHATOWAR): (a) to (d) Proposal for enactment of a Central Legislation for Construction Workers vis a vis the recommendations of the Lok Sabha Committee on Petitions on the Petition of the National Campaign Committee is under consideration of Government.

Tidal wave energy Projects

2081. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of tidal wave energy projects which have been envisaged in the Eighth Five Year Plan;

(b) what is the allocation of funds for this purpose; and

(c) whether Government have identified the locations for the tidal wave energy projects?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Two breakwater integrated wave energy projects have been proposed to be undertaken during the Eighth Five Year Plan. An amount of Rs. 30 crores has been projected in the Eighth Plan proposals for these two projects.

(c) The Thangassery Fishing Harbour in Kerala and Mus Point, in Car Nicobar Islands, where breakwaters are proposed to be constructed, have been identified for construction of breakwater integrated wave energy systems subject to techno-economic feasibility.